

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जुलाई, 2009 ई0 (आषाढ़ 27, 1931 शक सम्वत्)

[संख्या–29

1425

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें वार्षिक चन्दा पृष्ठ संख्या विषय ₹0 सम्पूर्ण गजट का मूल्य 3075 भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 1500 277-293 माग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया 1500 235-236 भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञिप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण 975 भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 975 भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 975 भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 975

स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग-1

अधिसूचना

08 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 541/XX(1)/126/सी0बी0आई0 जांच/2009—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, सन् 1946) की घारा 6 के प्राविधानों के अनुसरण में, उत्तराखण्ड के राज्यपाल, एतद्द्वारा श्री रणबीर सिंह पुत्र श्री रविन्द्र पाल हाल निवासी—साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ०प्र० मूल निवासी—खेकड़ा, जिला बागपत की मृत्यु के संबंध में जनपद देहरादून में पंजीकृत अभियोगों मु०अ०सं०—143/09 अंतर्गत घारा 394 माठद०वि०, थाना डालनवाला, मु०अ०सं०—98/09 अंतर्गत घारा 307 माठद०वि० थाना रायपुर, मु०अ०सं०—99/09 अंतर्गत घारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना रायपुर एवं मु०अ०सं०—101/09 अंतर्गत घारा 147, 148, 302, 506 माठद०वि० थाना रायपुर के अपराधों से जुड़े हुए या उससे संबंधित प्रयासों, दुष्ट्रोरणों और षड्यंत्रों तथा उसी संव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध (अपराधों) के अन्वेषण के लिए उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में शक्ति और अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु सहमित प्रदान करते हैं।

आज्ञा से.

सुमाष कुमार, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 541/XX(1)/126/CBI/2009**, Dehradun dated July 08, 2009 for general information:

NOTIFICATION

July 08, 2009

No. 541/XX(1)/126/CBI/2009--In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of Uttarakhand is pleased to accord consent to extend the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for investigation of Crime Nos. 143/09 U/S 394 I.P.C. P.S. Dalanwala, Distt. Dehradun, 98/09 U/S 307 I.P.C., 99/09 U/S 25 Arms Act P.S. Raipur, Distt. Dehradun and Crime no. 101/09 U/S 147, 148, 149, 302, 506 I.P.C. P.S. Raipur, Distt. Dehradun, Uttarakhand relating the death of Sh. Ranbir Singh S/o Sh. Ravindra Pal, R/o Shahibabad, Gaziabad (U.P.) permanent resident of Khekra, Distt. Bagpat in an alleged Police encounter or abetment and conspiracy in relation thereto or in connection with the aforesaid offences and any other offence/ offences committed in the course of the same transactions or arising out of the same facts.

By Order,

SUBHASH KUMAR, Principal Secretary, Home.

पशुपालन अनुभाग-1

अधिसूचना प्रकीर्ण 22 जन, 2009 ई०

संख्या 1255/XV-1/2(13)/2006—"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा में मर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2009

माग एक-सामान्य

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2009 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-सेवा की प्रास्थिति-

उत्तराखण्ड पशुपालन विमाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा में समूह "ख" एवं "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3-परिभाषायें--

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक, पशुपालन, विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो ''भारत का संविधान'' के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाये:
- (ग) "आयोग" से लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अमिप्रेत है;
- (घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
- (ङ) "निदेशक" से निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड अमिप्रेत है;
- (च) "अन्य पिछड़े वर्गों" से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं:
- (छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अमिप्रेत है:
- (ज) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अमिप्रेत है;
- (झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा अभिप्रेत है;
- (ण) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत हैं, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
- (ट) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
- (ठ) "मर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से आरम्म होने वाली बारह मास की अवधि अमिप्रेत है।

भाग दो-संवर्ग

4-सेवा का संवर्ग-

- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी 'परिशिष्ट' में दी गयी है :

परन्तू यह कि-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
- (दो) राज्यपाल ऐसे अस्थायी एवं स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

5-भर्ती का स्रोत-

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :--

- (एक) पशुधन प्रसार अधिकारी-
- (क) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;
- (ख) 10 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे विभागीय कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो-सीधी भर्ती द्वारा :

परन्तु यदि सीधी भर्ती के लिये पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त विभागीय कर्मचारी उपलब्ध न हों तो, पदों को खण्ड (क) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

- (ग) शासन की पूर्वानुमित से 5 प्रतिशत सेना के रिमाउन्ट पशुचिकित्सा कोर में पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा करने वाले श्रेणी−1 तथा श्रेणी−2 के सेवानिवृत्त पशुचिकित्सा ड्रेसरों में से।
- (दो) ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पशुधन प्रसार अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष की सेवा अतिदुर्गम/दुर्गम क्षेत्र में की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(तीन) क्षेत्र प्रबन्धक-कुक्कुट-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष की सेवा अतिदुर्गम/ दुर्गम क्षेत्र में की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

6--आरक्षण--

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार-अईताएं

7-राष्ट्रीयता-

सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भातीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना सूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अविध के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8-शैक्षिक अर्हताएं-

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/ कृषि/पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9-अधिमानी अर्हता--

अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

- (क) नेशनल कैंडिट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
- (ख) एन०एस०एस० का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
- (ग) रिमाउन्ट वैटरीनरी कोर में वैटरीनरी ड्रैसर श्रेणी−1 तथा श्रेणी−2 के रूप में निरन्तर 15 वर्ष की सक्रिय सेवा की हो।

10-प्रशिक्षण-

(1) पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिये चयनित किसी अभ्यर्थी से, नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण, जैसा समय—समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाय, पर जाने की अपेक्षा की जायेगी :

परन्तु ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जो नियम 9 के खण्ड (ग) में विहित अधिमानी अर्हतायें रखता हो, उक्त प्रशिक्षण में जाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि नियम 5 के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) के अधीन भर्ती किये गये अभ्यर्थी के लिये उक्त प्रशिक्षण की अवधि ऐसी अवधि तक, जैसा सरकार आवश्यक समझे, शिथिल की जा सकती है।

- (2) नियम 5 के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) के अधीन चयनित कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अविध के दौरान पद के चयन के ठीक पूर्व लागू पशुधन प्रसार अधिकारी के पद का अनुमन्य वेतन प्राप्त करेगा।
- (3) प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थी से कम से कम दो वर्ष सेवा में बने रहने का एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जायेगी।

11-आय्-

सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद एक जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जानी है, उस वर्ष की एक जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद एक जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जानी है, उसे उस वर्ष की एक जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाये, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

12-चरित्र--

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये समी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराघ के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13-वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अध्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अध्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

14--शारीरिक स्वस्थता--

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच-भर्ती प्रक्रिया

15-रिक्तियों का अवधारण-

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों तथा विमाग में कार्यरत अभ्यर्थियों एवं सेना के रिमाउण्ट पशु—चिकित्सा कोर से सेवानिवृत्त के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

16-सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(एक) "नियुक्ति प्राधिकारी"-

अध्यक्ष

- (दो) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी, को "नियुक्ति प्राधिकारी" द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा— सदस्य
- (तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई भी अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा—
- (चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई वरिष्ठ अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से मिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा—
- (2) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन—पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक सभाचार—पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन—पत्र उपनियम (2) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमन्त्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा :—
 - (एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,
 - (दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा कर, या रेडियो / दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके,
 - (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके, और
 - (चार) उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करके।
- (4) चयन के लिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type Questions with Multiple Choice) की होगी।
 - (5) लिखित परीक्षा में जीव विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा।
 - (6) छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे।
- (7) प्रश्न-पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (8) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (9) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (10) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित या व्यापक परिचालन वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।
- (11) चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों एवं अन्य मूल्यांकनों के कुल योग के आधार पर प्रवीणता के क्रम में अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर—बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(12) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित या दैनिक समाचार-पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, प्रकाशित किया जायेगा।

17-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

- (1) पदोन्नित द्वारा भर्ती नियम 16 के उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मापदण्ड) नियमावली, 2004 के अनुसार की जायेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) चयनोन्नित पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
- (3) चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

माग छ:-नियुक्ति,परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18-नियुक्ति-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 16 और 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों। पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए नियुक्ति के प्रथम पाँच वर्ष तक अति दुर्गम/दुर्गम क्षेत्र में सेवा करना बाध्यता है।
- (2) यदि एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति, चयन में यथा-अवधारित या उस संवर्ग में, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया हो, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

19-परिवीक्षा-

- (1) सेवा में किसी पद पर था उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर घारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमित दे सकता है।

20-स्थायीकरण-

(1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि-

- (क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय,
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाघान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।
- (2) जहाँ समय—समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहाँ उक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

21-ज्येष्ठता-

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात-वेतन इत्यादि

22-वेतनमान-

- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्म के समय प्रवृत्त वेतनमान 'परिशिष्ट' में दिये गये हैं। 23-परिवीक्षा अविध में वेतन-
- (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तब दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अविध पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब एक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो सरकार के अधीन पहले से कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अविध में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अविध बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अविध की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत निमयों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ-अन्य उपबन्ध

24-पक्ष समर्थन--

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

25-अन्य विषयों का विनियमन--

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

26-सेवा शर्तों में शिथिलता-

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित किठनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

27-व्यावृत्ति-

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रमाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम-4(2) देखें]

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान (रु० में)	पद संख्या
1	2	3	4
1.	पशुघन प्रसार अधिकारी	5200-20200 (ग्रेड पे-2800)	882
2.	ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	9300-34800 (ग्रेंड पे-4200)	
3.	क्षेत्र प्रबन्धक-कुक्कुट	9300-34800 (ग्रेंड पे-4200)	01
	योग		893

आजा से.

अमरेन्द्र सिन्हा, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1255/XV-1/2(13)/2006**, dated June 22, 2009 for general information:

NOTIFICATION

Miscellaneous

June 22, 2009

No. 1255/XV-1/2(13)/2006--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India", and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Animal Husbandry Department Livestock Extension and Poultry Development Service.

THE UTTARAKHAND ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT LIVESTOCK EXTENSION AND POULTRY DEVELOPMENT SERVICE RULES, 2009

Part I--General

1--Short title and Commencement--

- (1) These rules may be called "The Uttarakhand Animal Husbandry Department Livestock Extension and Poultry Development Service Rules, 2009".
 - (2) These Rules shall come into force at once.

2--Status of the Service--

The Uttarakhand Animal Husbandry Department Livestock Extension and Poultry Development Service comprises Group 'B' and 'C' posts.

3--Definitions--

In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or context--

- (a) "Appointing Authority" means the Director, Animal Husbandry, Uttarakhand;
- (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part--II of the Constitution;
- (c) "Commission" means the Uttarakhand Public Service Commission;
- (d) "Constitution" means the Constitution of India;
- (e) "Director" means the Director, Animal Husbandry, Department Livestock Extension and Poultry Development, Uttarakhand;
- (f) "The Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Service (Reservations of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (as applicable to the State of Uttarakhand);
- (g) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
- (h) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;
- (i) "Service" means the Uttarakhand Animal Husbandry Department Livestock Extension and Poultry Development Service;
- "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules, if there were no rules, in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being, by executive instructions issued by the Government;
- (k) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the Service;
- (I) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II-Cadre

4--Cadre of Service--

- (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such, as may be determined by the Governor from time to time.
- (2) The strength of the service and of each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix:

Provided that

- (i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor, may hold in abeyance, any vacant post without thereby entitling any person to compensation;
- (ii) The Governor may create such additional temporary or permanent posts, as he may consider proper.

Part'Ill-Recruitment

5--Source of Recruitment--

Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources, namely:--

(1) Livestock Extension Officer:

- (A) 85 percent by direct recruitment.
- (B) 10 percent by direct recruitment from amongst substantively appointed Departmental candidates who have put in five years continuous service in the Uttarakhand Animal Husbandry Department on the first day of the year of the recruitment and must have passed the Intermediate examination with Biology or Agriculture as one of the subjects of the Board of Intermediate Education and Examination, Uttarakhand or Board of Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto:

Provided that sufficient number of eligible or suitable departmental candidates are not available for direct recruitment, the posts shall be filled by direct recuitment, under clause (A).

(C) 5 percent from amongst the retired the Veterinary Dressers Grade-1 and Grade-2 with 15 years regular service in the Remount Veterinary Core of the Army with prior sanction of the Government.

(2) Senior Poultry Inspector:

By promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Livestock Extension Officers who have completed ten years' service, as such on the first day of the year of the recruitment out of which at least five years service should be in difficult/very difficult remote areas.

(3) Farm Manager (Poultry):

By promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Senior Poultry Inspectors who have completed fifteen years' service, as such on the first day of the year of recruitment out of which at least five years service should be in difficult/very difficult remote areas.

6--Reservation--

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part IV-Qualifications

7--Nationality--

A candidate for direct recruitment to the Service must be--

- (a) A citizen of India; or
- (b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) A person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) above will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note --A Candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8--Academic Qualifications--

A candidate for direct recruitment to the Service must have passed the Bachelor's degree from a University established by law in India with Biology or Agriculture or Animal Husbandry as in any one of the subjects.

9--Preferential Qualifications--

A candidate who has--

- (a) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, or
- (b) Obtained a 'N.S.S. certificate, or
- (c) Served in Remount Veterinary Core for continuous fifteen years active service as Veterinary Dressers Group I and Group II.

10--Training--

(1) A candidate selected for the post of Livestock Extension Officer shall be required to undergo such training for a period of minimum two years or such training as may be prescribed by the Government from time to time prior to his appointment:

Provided that a candidate possessing preferential qualifications prescribed in clause (C) of rule 9 shall not be required to undergo the said training:

Provided further that the period of said training for the candidate recruited under sub clause (b) of clause (1) of rule 5 may be relaxed upto the period as the Government may deem necessary.

- (2) A candidate selected under sub clause (b) of clause (1) of rule 5, during the period of training, will get the pay admissible for the post of Livestock Extension Officer, immediately before the selection to the post.
- (3) After completion of the training the candidate shall be required to execute at least two years bond to continue to remain in service.

11--Age--

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January, 01 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period from January 01 to June 30 and on July, 01 if the posts are advertised during the period from July 01 to December 31:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be higher by such number of years as may be specified.

12--Character--

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself in this respect.

Note--Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

13--Marital Status--

A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

14--Physical Fitness--

No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule, 10, contained in Chapter III of the Financial handbook, Volume II, Part III:

Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V-Procedure for Recruitment

15--Determination of Vacancies--

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories and departmental candidates and vacancies reserved for Army Remount Animal Husbandry Core retired personal, under Rule 6.

16--Procedure for Direct Recruitment--

- (1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a selection committee comprising :--
 - (A) Appointing Authority--

Chairman

- (B) A senior officer having adequate knowledge in the related field according to the requirement of the posts for which recruitment each to be made shall be nominated by the Appointing Authority-- **Member**
- (C) An officer belonging to the Scheduled Castes or Schedule Tribes, nominated by the Appointing Authority, if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Schedule Tribes. If the Chairman belongs to Scheduled Castes or Schedule Tribes an officer belonging to other than Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Appointing Authority-
 Member
- (D) A senior officer belonging to the Other Backward Classes, nominated by the Appointing Authority, if the Chairman does not belong to Other Backward Classes. If the Chairman belongs to Other Backward Classes an officer belonging to other than Backward Classes or Scheduled Castes or Schedule Tribes shall be nominated by the Appointing Authority—

 Member
- (2) For the Direct Recruitment, the application in prescribed format shall be published by the Appointing Authority in at least two such daily newspapers which are widely circulated.
- (3) For Direct Recruitment the Appointing Authority shall invite applications in the prescribed format published in sub-section (2) and notify the vacancies in the following manner:--
 - (i) By issuing to advertisement in daily newspapers which are widely circulated. By affixing notice on the Notice Board of office.
 - (ii) Advertising through Radio/T.V. and other employment newspaper,
 - (iii) Notifying the vacancies to the Employment Exchange and
 - (iv) By displaying on the official website of the State of Uttarakhand.
 - (4) The Objective Type written test with multiple choice for selection shall carry 100 marks.
- (5) The written test shall consist of single question paper which will include questions related to Biology, Agriculture and Animal Husbandry.

- (6) For retrenched employees five marks will be awarded for each completed year of service and subject to maximum 15 marks.
- (7) While evaluating the question paper one mark will be awarded for each correct answer and 1/4 mark will be deducted for each incorrect answer.
- (8) Candidates will be allowed to carry back the question booklet of written examination with them after the examination.
- (9) Answer sheet of the written Examination shall be in duplicate (including the carbon copy) and candidate shall be allowed to carry back the carbon copy with him after the examination.
- (10) Answer key of written examination will be published on the official website of the State of Uttarakhand or published in widely circulated newspapers, after the examination.
- (11) The selection committee shall prepare the final selection list in order of proficiency on the basis of the aggregate of marks obtained by each candidate in the written examination and other evaluations. If two or more candidates equal marks in the aggregate the candidate obtaining more marks in the written examination shall be pleased higher in the selection list. If two of more candidates obtain equal marks in the written examination also the candidate senior in age will be placed higher in the selection list. The number of the names in the selection list shall be more (but not more than 25 percent) than the number of Vacancies. The selection committee will forward the list to the Appointing Authority.
- (12) Along with the declaration of selection result, marks of obtained by all the candidates in the written examination will be displayed on Uttarakhand website www.ua.nic.in or published in daily newspaper having wide circulation.

17--Procedure for Recruitment by Promotion--

- (1) Recruitment by promotion shall be made through the selection committee constituted under sub rule (1) of rule 16 in accordance with the Uttarakhand Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004.
- (2) The Appointing Authority shall prepare eligibility list of the candidates, in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection (for the Post Outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003, and place the same before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.
- (3) The selection committee shall prepare a list of selected candidates on the basis of the records, referred to in sub rule (2) and if it considers necessary.
- (4) The selection committee shall prepare a list of selected candidates, according to the Government orders in force the time of recruitment and forward the same to the Appointing Authority.

Part VI-Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

18--Appointment--

- (1) The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 16, or rule 17, as the case may be. It is mandatory for Livestock Extension Officer to serve in difficult/very difficult remote areas for the first five years of his appointment.
- (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

19--Probation--

- (1) A person an appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

- (3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.
- (5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

20--Confirmation--

- (1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--
 - (a) his work and conduct is reported to be satisfactory.
 - (b) his integrity is certified, and
 - (c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
- (2) Where confirmation is not necessary according the provisions of the Uttarakhand Government Servant Confirmation Rules, 2002 as amended from time to time the order declaring under sub-rule (3) of rule 5 of the said rules that the respective person has successfully completed the probation period and shall be deemed to be the order of confirmation.

21--Seniority--

The *Inter se* seniority of persons substantively appointed to a post in the Service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

Part VII-Pay Etc.

22--Sclae of Pay--

- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
 - (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in the Appendix.

23--Pay during Probation--

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year's satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority duets otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Part VIII-Other Provisions

24--Canvassing--

No recommendations, either written or oral, other than those required under rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

25--Regulation of Other Matters--

In regard to matters not specifically covered by these rules, or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to Government servants, serving in connection with the affairs of the State.

26--Relaxation in the Conditions of Service--

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons, appointed to the Service, causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

27--Relaxation in the Conditios of Service--

Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the Government orders issued from time to time in this regard.

APPENDIX
[Please See Rule 4 (2)]

SI.No.	Designation	Pay Scale	No. of Post	
51.NO.	2	3	4	
<u>-</u>	Livestock Extension Officer	5200-20200 (Grade pay-2800)	882	
1. 2.	Senior Poultry Inspector	9300-34800 (Grade Pay-4200)	10	
	Farm manager (Poultry)	9300-34800 (Grade Pay-4200)	01	
3.	Total		893	

By Order,

AMRENDRA SINHA, Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जुलाई, 2009 ई0 (आषाढ़ 27, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 06, 2009

No. 118/UHC/Admin. A/2009.—On the basis of recommendations of Hon'ble Shetty Pay Commission and in terms of G.O. No. 1023/I-1-2003-18(5)/2001, dated 26.05.2003 read with G.O. No. 2017/I-1-03-18(5)/2001, dated 29.09.2003 issued by Government of Uttarakhand, the Court has been pleased to grant 1st A.C.P. pay scale of Rs. 10750-300-13150-350-14900 to the following Judicial Officers on completion of their five years of continuous services in Civil Judge (Jr. Div.) Cadre, from the date mentioned against their names:

SI. No.	Name of the Officer	Date of completion of 05 years of service	Date of A.C.P.	
1.	Smt. Shabad Bano	19.09.2008	20.09.2008	
2.	Sri Nasseem Ahmad	21.09.2008	22.09.2008	
3.	Sri Abdul Qayyum	21.09.2008	22.09.2008	
4.	Sri Om Kumar	21.09.2008	22.09.2008	
5.	Sri Sanjeev Kumar	19.09.2008	20.09.2008	
6.	Sri Nandan Singh	22.09.2008	23.09.2008	

By Order of the Court,

Sd/-

RAVINDRA MAITHANI,

Registrar General.

July 07, 2009

No. 119/UHC/XIV/88/Admin. A--Sri Naseem Ahmad, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, Distt. Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned medical leave for 11 days w.e.f. 15.06.2009 to 25.06.2009.

July 07, 2009

No. 120/XIV/37/Admin. A/2008--Sri Arun Vohra, Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 03.06.2009 to 19.06.2009.

July 07, 2009

No. 121/UHC/XIV/29/Admin. A--Sri Raj Krishna, District & Sessions Judge, Pauri Garhwal, is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 22.06.2009 to 27.06.2009.

July 07, 2009

No. 122/UHC/XIV/70/Admin.A--Sri Manish Mishra, Chief Judicial Magistrate, Champawat, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 22.06.2009 to 01.07.2009 with permission to prefix 21.06.2009 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).